

03 साफला एकादशी 2025, कब है 14 या 15 दिसंबर ?

06 ...डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता

08 सीवरनैन वेलफेयर यूनिन अमृतसर द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन

परिवहन आयुक्त द्वारा विभाग में तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर जनता को सीधे और परोक्ष दोनों तरह के नुकसान में डाल दिया, जाने विश्लेषण

संजय बाठवा

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में एमवीआई (Motor Vehicle Inspector) के लिए तकनीकी योग्यता दिल्ली के आधिकारिक भर्ती नियमों में साफ-साफ दी गई है, जबकि एमएलओ/डीटीओ के लिए नियम हाल में संशोधित हुए हैं और उनमें तकनीकी योग्यता का स्तर पद की प्रकृति के अनुसार रखा गया है।

एमवीआई (Motor Vehicle Inspector) — दिल्ली दिल्ली सरकार के 2021 के भर्ती नियमों के अनुसार एमवीआई के लिए अनिवार्य तकनीकी योग्यता यह है:

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास
2. 3 वर्ष का डिप्लोमा (Diploma) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हो।

3. ऐसा वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जो गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटर वाहन (Light Motor Vehicles) चलाने की अनुमति देता हो।
4. ये सभी शर्तें "Essential Qualification" के रूप में लिखी गई हैं, यानी इनके बिना सामान्यतः सीधे भर्ती (Direct Recruitment) नहीं हो सकती।

एमएलओ / डीटीओ (Motor Licensing Officer / District Transport Officer) — दिल्ली में एमएलओ के पद को हाल में पुनर्गठित कर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (DTO) के रूप में रीडिजाइन किया गया है; यह पद फोल्ड-लेवल पर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट आदि का दायित्व निभाता है।

2025 में जारी डीटीओ के संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार, डिप्लोमा/प्रमोशन के लिए उम्मीदवार के पास आम तौर पर लेवल-6 या समकक्ष पद पर सेवा के साथ मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से संबंधित डिप्लोमा / तकनीकी योग्यता की शर्तें रखी गई हैं (सटीक शब्दावली नोटिफिकेशन में दी गई है)।



डीटीओ जैसे पदों के लिए जब नियमों में स्पष्ट तकनीकी योग्यता (मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल डिप्लोमा आदि) अनिवार्य की गई हो, और फिर भी बिना इस योग्यता वाले अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, तो इससे जनता को सीधे और परोक्ष दोनों तरह के नुकसान हो सकते हैं।

सड़क सुरक्षा और फिटनेस पर असर डीटीओ/आरटीओ अधिकारी वाहन पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट, ओवरलोडिंग, ब्रेक-लाइट, टायर, उत्सर्जन आदि की निगरानी करते हैं; तकनीकी समझ कम होने पर अनफिट वाहन भी सड़क पर चलने की अनुमति पा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और जान-माल की हानि का जोखिम बढ़ जाता है।

तकनीकी ज्ञान न होने से नए वाहन मानक, सुरक्षा फीचर, और उत्सर्जन नियम (जैसे BS-VI, क्रैश नॉर्स) समझने व लागू करने में चुक हो सकती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के उद्देश्य — सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन — के विपरीत है।

भ्रष्टाचार, मनमानी और पारदर्शिता की कमी तकनीकी मानकों की सूक्ष्म समझ न होने पर निरीक्षण अधिक "कागजी" या व्यक्तिपरक हो जाता है; ऐसी स्थिति में जानकार दलाल तथा वाहन मालिक नियमों की कमजोर समझ का फायदा उठाकर घुस या दबाव के जरिए गलत काम निकलवा सकते हैं।

जब बिना योग्यता वाले लोग तकनीकी फैसले ले रहे हैं, तो विभाग की निष्पक्षता और विश्वास नीयता पर सवाल उठते हैं, जिससे शिकायतें, मुकदमे और प्रशासनिक अविश्वास बढ़ सकता है।

नीति-निर्माण और रोड सेफ्टी रणनीति पर प्रभाव डीटीओ स्तर पर दुर्घटना विश्लेषण, ब्लैक-स्पॉट की पहचान, वाहन-डिजाइन से जुड़े पैटर्न, और स्थानीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाना होता है; तकनीकी पृष्ठभूमि न होने पर यह विश्लेषण सतही रह जाता है और प्रभावी नीति नहीं बन पाती।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और अन्य विशेषज्ञ निकायों ने ही सिफारिश की है कि

मोटर वाहन विभाग के उच्च पदों पर तकनीकी योग्यता जरूरी हो, ताकि वे वैज्ञानिक साक्ष्यों और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले सकें; इस मानक से विचलन जनता के हित के विपरीत माना जाता है।

कानून के उद्देश्य और बराबरी के अधिकार पर चोट मोटर व्हीकल एक्ट एक कल्याणकारी (welfare) कानून है, जिसका मकसद लोगों की जान की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात है; जब जानबूझकर तकनीकी योग्यता की शर्तों को अनदेखा कर नियुक्ति होती है, तो कानून का यही मूल उद्देश्य कमजोर हो जाता है।

योग्य तकनीकी उम्मीदवारों के लिए यह अनुचित प्रतिस्पर्धा (unfair competition) बनती है, जिससे उनके समान अवसर (आर्टिकल 14 और 16 के तहत) प्रभावित होते हैं; लंबी अवधि में इससे विभाग में प्रतिभाशाली तकनीकी लोगों के आने की प्रेरणा भी घटती है, जिसका नुकसान अंततः जनता को ही उठाना पड़ता है।

जय जगन्नाथ जी

जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन

(दिल्ली से प्लाइट द्वारा यात्रा)

यात्रा तिथि: 19 जनवरी से 21 जनवरी

यात्रा कार्यक्रम:

DAY 1 — दिल्ली भुवनेश्वर (प्लाइट द्वारा)
होटल में चेक-इन
खंडगिरी एवं उदयगिरी गुफाएं
एलिफैंटा / लायन / क्वीन के क्लस
लिंगराज मंदिर
जैन मंदिर
मुवतेश्वर मंदिर
बिंदुसागर
रात्रि विश्राम — भुवनेश्वर

DAY 2
नाशता
बुद्ध स्तूप
कोणार्क सूर्य मंदिर
चंद्रभागा बीच

रामचंडी मंदिर
पुरी होटल में ठहराव
श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन
विमला शक्तिपीठ
रात्रि विश्राम — पुरी

DAY 3
नाशता
चिल्का झील (ऑफिकन सैंक्चुरी)
दिल्ली वापसी

पैकेज में शामिल:
हवाई यात्रा
होटल ठहराव
केवल नाशता

पैकेज मूल्य: 25,000 /-
प्रति व्यक्ति

बुकिंग अंतिम तिथि:
15 दिसंबर

संपर्क करें:
9716338127,
9811732094
9212632095



दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, GRAP-4 लागू; जानें किन-किन चीजों पर लगी पाबंदियां



दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू

परिवहन विशेषज्ञ

नई दिल्ली। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि एक ही दिन में दो बार ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) बदलना पड़ गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुबह ग्रेप तीन लगाने की घोषणा की तो शाम को ग्रेप चार लागू किया गया। इसी के साथ अब एनसीआर भर में ग्रेप के चारों चरणों की पाबंदियां लागू हो गई हैं।

दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही। एक्यूआई 397 के साथ 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया। शाम चार बजे यह 431 था, जो शाम छह बजे बढ़कर 441 और रात आठ बजे 452 हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में

एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एक्यूआई वजीरपुर में सबसे अधिक 445, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439 और अशोक विहार व रोहिणी दोनों जगह 437 दर्ज किया गया। नरेला में 432, पटपड़गंज में 431, मुंडका में 430 और बवाना, चांदीओ एवं नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक और पंजाबी बाग में एक्यूआई 423 दर्ज किया गया, जबकि सिरी फोर्ट और सोनिया विहार में यह 424 रहा।

सीपीसीबी ने बताया कि बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 414 दर्ज हुआ, इसके बाद कर्णा सिंह शूटिंग रेंज में 409, नार्थ कैम्पस और आरके पुरम में

408-408 तथा ओखला फेज-2 में 404 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।

इन चीजों पर रोक
ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार डीजल के चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा (लेकिन अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिव्यांग दोनों ही श्रेणी के वाहन चला सकेंगे)। स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले ईंटे भट्टे, हाट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को दिल्ली-एनसीआर में बंद किया जाएगा।

ग्रेप चार के प्रतिबंधों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, प्लांट/ओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से

जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक रहती है। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी चीजें लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों, और बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पंजीकृत बीएस छह या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर रोक रहेगी।

छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई आनलाइन या हाइब्रिड मोड में की जा सकती है। सरकारी और सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया जा सकता है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

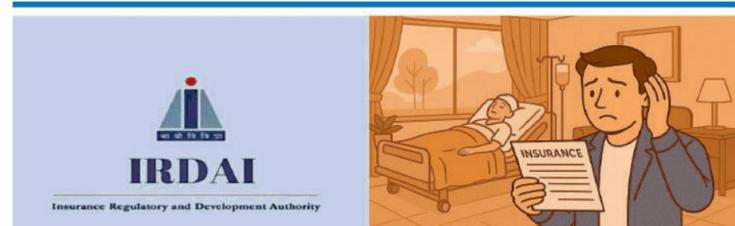
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com



पंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार

IRDAI / इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन बनकर टगी के मामले बढ़ रहे हैं



ठग लैपस हो चुकी बीमा पॉलिसियों की असली जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को IRDAI, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, या बीमा कंपनी का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं। वे "पेंडिंग रिफंड" का झांसा देते हैं और प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल एक्टिवेशन, NOC, GST, या RBI बैंड के नाम पर पैसे मांगते हैं।

मामला 1 — दिल्ली (₹1.3 लाख की टगी) चार लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने IRDAI और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन अधिकारी बनकर एक केंसर पॉइंट व्यवस्थित से क्लॉक-उसका-मैडिकल इंश्योरेंस रिफंड 'प्रोसेसिंग चार्ज' देने पर ही मिलेगा — और उससे ₹1.3 लाख टग लिए।

मामला 2 — मुंबई (₹2.36 करोड़ की टगी) एक सेवानिवृत्त नागरिक से टगी IRDAI, NSDL और NPCI के अधिकारी बनकर बात की और सात लैपस

पॉलिसियों का रिफंड दिलाने का वादा किया। बाद में "RBI क्लियरेंस", "बैंड फीस", और "टैक्स एडजस्टमेंट" के नाम पर लगातार पैसे लेते रहे — कुल नुकसान ₹2.36 करोड़।
टगी कैसे होती है (संक्षेप में)
1. असली डेटा का दुरुपयोग — लोकल आईडी पॉलिसी जानकारी, फर्जी KYC कॉल, एक्सप्रेस रीमिडियर।
2. अधिकारियों को नकल — नकली IRDAI/ऑम्बड्समैन अधिकारी, स्पूफ़ नंबर, फर्जी ID।
3. विश्वास का जाल — पॉलिसी नंबर, प्रीमियम, लैपस डेट जैसे असली जानकारी बताते हैं।
4. पैसे की मांग — बैंक ट्रांसफर/UPI या नकली रिफंड पोर्टल के

जरिए फ्रीस मांगते हैं।
5. बार बार नए शक — "फाइल RBI में अटक है", "TDS/GST/NOC देना होगा"।
6. गायब हो जाना — फोन बंद, व्हाट्सएप/डिजिटल, पैसा तुरंत निकाल लेते हैं।
लोग क्यों फंस जाते हैं
* असली पॉलिसी जानकारी मिलने से भरोसा हो जाता है
* IRDAI की प्रक्रिया की जानकारी कम होती है
* कॉलर ID स्पूफिंग
नागरिकों के लिए सुरक्षा चेकलिस्ट
✓ IRDAI कभी रिफंड के लिए कॉल नहीं करता
✓ किसी भी बीमा रिफंड के लिए कोई

शक नहीं लगता
✓ हर कॉल को बीमा कंपनी के आधिकारिक नंबर पर वेरिफाई करें
✓ अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसी अनजान व्यक्ति को न भेजें
✓ तुरंत रिपोर्ट करें → 1930 | cybercrime.gov.in
आउटरीच संदेश
1. IRDAI रिफंड के लिए कभी कॉल नहीं करता।
2. इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन कोई फीस नहीं मांगता। किसी रिफंड के लिए 'प्रोसेसिंग चार्ज', 'RBI बैंड' या 'फाइल एक्टिवेशन' की जरूरत नहीं होती। अगर कोई रिफंड दिलाने के नाम पर पैसे मांगे — यह टगी है। रिपोर्ट करें: 1930 या cybercrime.gov.in

ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो मांगने पर नहीं देनी चाहिए, उनको देने से घर आर्थिक रूप से संकट आ सकता है, और जातक के ग्रह भी खराब हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका लेन देन करने से भाग्य भी रूठ सकता है

पंकी कुंडू
हल्दी हल्दी किसी को मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए, हल्दी देने से लक्ष्मी जाती है। हल्दी घर में कभी खत्म भी नहीं होनी चाहिए, कि आप को भी किसी से मांगना पड़े।
झाड़ू झाड़ू भी किसी को मांगने पर नहीं देनी चाहिए, ये भी लक्ष्मी होती है।
दही (जामन) जामन भी किसी को देने से बचना चाहिए, अगर किसी कारण वश देना भी पड़े, तो वार देख कर देना चाहिए और दोनों टाइम मिलने पर नहीं देना चाहिए।
नमक नमक का भी आदान प्रदान कम करना चाहिए, कहते हैं कि किसी के नमक का कर्ज अगले जन्म तक नहीं उतार सकते।
सरसों का तेल सरसों के तेल का भी आदान प्रदान कम ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये शनि से संबंधित होता है।
दूध दूध भी मांगने से जल्दी से नहीं देना चाहिए, जब तक कोई खास मजबूरी न हो, यदि ऐसा हो तो आर्थिक रूप से तनाव शैलना पड़ता है।
चांदी चांदी का भी देन लेन कम ही करे, चांदी को ना बेचे और ना गिफ्ट करे, चांदी के बदले चांदी ही खरीद ले, और चांदी गिफ्ट करने से घर की खुशियां जाती हैं, ऐसी मान्यता गाया है।
मोबाइल मोबाइल भी किसी के मांगने पर कम ही दे, जहां तक संभव है मना ही करना बेहतर होगा, सामने वाला मोबाइल से कुछ भी छेड़खानी कर सकता है।
कपड़ों का आदान प्रदान एक दूसरे के पहने हुए आ

कपड़ों का कम ही इस्तेमाल करें, इससे त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, साथ ही खुद के ग्रह भी खराब होने का डर रहता है।
जूठा भोजन अपना जूठा भोजन अगर बच गया है, जातक नहीं खा पा रहा है तो अपने घर के ही किसी परिजन दे देना चाहिए, ऐसा करने से ये मान्यता है कि घर की लक्ष्मी घर में ही रहेगी।
अन्यों के साथ एक ही थाली में खाना मेहमानों के साथ अलग ही पात्रों में भोजन करना चाहिए, एक साथ भोजन करने से यदि मेहमान के ग्रह अशुभ हैं और मेजबान के अच्छे हैं तो अच्छे ग्रह होते हुए भी मेहमान के अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाएंगे।
शनि की लोहे की अंगुठी देना अगर जातक ने शनि की अंगुठी (लोहे की) पहन रखी है तो कभी भी दूसरे के मांगने पर ना देनी चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अन्यों को लाभ पहुंचता है।
धनतेरस वाले दिन दीपक का ध्यान रखना, विशेष कर कोड़ी का धनतेरस वाले दिन सभी के यहां दीपक जलाया जाता है, उसमें कानी कोड़ी या सिक्का डाला जाता है, उसे संभाल कर रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है कि वह कोई चुरा ना पाए, उससे जुआ खेलने से जुआरी अधिकतर जीतते हैं, दिवाली के समय वैसे भी बहुत जुआ होता है। यदि सावधानी न बरती जाए तो आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
दीपावली पर झाड़ू का ध्यान रखना दीपावली के अवसर पर झाड़ू का लेन देन नहीं करना चाहिए अमूमन झाड़ू मांग लिया जाता है दीपावली पर विशेष कर झाड़ू का

ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग झाड़ू चोरी की ताक में रहते हैं।
ताजमहल ताजमहल उपहार में देने से बचना चाहिए, इससे रिश्ते टूटने का भय रहता है।
चप्पल चप्पल का भी लेन देन से बचना चाहिए, अन्यों की चप्पल पहनने से उनके अशुभ ग्रहों का प्रभाव आने लगता है यदि चप्पल चोरी हो जाए तो यह एक शुभ संकेत है परंतु बदले में अन्यों की चप्पल भी नहीं पहनकर आनी चाहिए।
रूमाल दूजों के रूमाल को भी लेने से बचना चाहिए और अपना रूमाल किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, यदि ऐसा भूल वश हो भी जाए तो याद आने पर तुरंत मांग ले, वरना रिश्ते टूटने का भय रहता है।
यू तो आधुनिक युग में युवा वर्ग ये सब पुरानी बातों पर कम ही ध्यान देते हैं, उन्हें ये सब बातें दृष्टिगोचर नहीं लगती हैं, फिर उनकी दोस्ती, जिसने जो प्यार से मांगा, उसको वह दे दिया अथवा उसका पहन लिया, वह यह सब अनजाने में करते हैं।
हमारे बुजुर्ग जो बात कहते थे, वह सही होता था, कुछ लोग आज भी उनका अनुसरण करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमारी शायद आखरी ही पीढ़ी है, जो काफी कुछ जानती और समझती है, कहते हैं experience is a good teacher.
हमने जो अपने कुछ कड़वे और कुछ अच्छे अनुभव से सीखा है, वो अनमोल सीख पीढ़ी में बांट जाए और आज कल के युवा वर्ग को भी चाहिए कि इस अनमोल खजाने से बंचित न रहें।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

डायबिटीज वाले लोगों को किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए — यह सब शोध-आधारित पोषण विज्ञान और विश्वसनीय मार्गदर्शन पर आधारित है।

डायबिटीज होने पर किन चीजों से बचें / सीमित करें डायबिटीज (या प्री-डायबिटीज) के दौरान, निम्नलिखित भोजन और पेय पदार्थों से बचना या इनकी मात्रा कम करना अच्छा रहता है। शोध बताता है कि ये खुराक ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं, इंसुलिन रोधी (insulin resistance) बढ़ा सकती हैं, तथा लम्बे समय में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकती हैं।

कैफ़ेकॉल्ड जैसे सीरियल्स में शुगर और रिफ़ाईंड कार्ब्स अधिक होते हैं; भोजन के तुरंत बाद ग्लूकोज अचानक बढ़ सकती है।
4. मिठाई, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, आइसक्रीम — इनमें शुगर और अस्वस्थ वसा (अनहेल्दी फैट्स) होती है; ब्लड शुगर अस्थिरता, अतिरिक्त कैलोरी और वजन बढ़ने का जोखिम रहता है।
5. तली हुई एवं डीप-फ्राइड चीजें — फ्रेंच फ्राइज, समोसा, पकोड़ा, चिप्स, अन्य स्नैक्स जो तेल-वसा में तले गए हैं; ये इंसुलिन रोधी, मोटापे व अन्य जटिलताओं की दिशा में ले जा सकते हैं।
6. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और पैकेज्ड स्नैक्स / फ़ास्ट फूड — इनमें अक्सर रिफ़ाईंड कार्ब्स, अतिरिक्त शुगर, अस्वास्थ्यकर वसा, और संरक्षक (preservatives) होते हैं — डायबिटीज प्रबंधन के लिए ये अनुकूल नहीं।
7. पूरा फ़ैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, उच्च-फैट मीट या प्रोसेस्ड मीट — अधिक संतृप्त वसा और

संसाधित मांस से इंसुलिन संवेदनशीलता बिगड़ सकती है, हृदय रोग व अन्य जोखिम बढ़ सकते हैं।
क्या बेहतर विकल्प बन सकते हैं साबुत अनाज (ब्राउन राइस, बाजरा, क्विनोआ), होल-ग्रेन ब्रेड या पास्ता, साबुत अनाज से बनी नाश्ते की चीजें।
1. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ — ताज़ा फल-सब्जियाँ, दल-पल, फलियाँ (legumes), जो शुगर अवशोषण को धीमा करते हैं।
2. लीन (lean) प्रोटीन स्रोत — मछली, चिकन, दालें, टोफू — प्रोसेस्ड मीट की बजाय।
3. शुगर मुक्त या बिना शुगर वाले पेय - पानी, बिना शुगर वाली चाय/काफ़ी, स्पार्कलिंग वॉटर आदि।
क्यों यह सलाह वैज्ञानिक रूप से मायने रखती है ?
1. ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) और ग्लाइसेमिक लोड (GL): जिन खाद्यों का GI/GL

अधिक होता है, वे तेजी से पचते और शुगर ब्लड में जल्दी छोड़ते हैं — इससे इंसुलिन की अचानक वृद्धि होती है। बार-बार यह होने पर इंसुलिन रोधी गुण (insulin resistance) बढ़ सकता है।
2. फाइबर की कमी: फाइबर भोजन को धीरे पचता है, शुगर अवशोषण धीमा करता है और ब्लड शुगर के अस्थिर उछालों को कम करता है। रिफ़ाईंड अनाज या प्रोसेस्ड कार्ब्स से ये लाभ नहीं मिलता।
3. अस्वास्थ्यकर वसा (saturated/trans fats) व प्रोसेस्ड मीट: यह वसा इंसुलिन की संवेदनशीलता कम कर सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल और हृदय-सम्बंधी जोखिम बढ़ा सकती हैं — जो कि डायबिटीज वाले के लिए ख़तरा और भी बढ़ा देती हैं।
4. मोटापा व मेटाबॉलिक तनाव: लगातार तले हुए, मीठे व प्रोसेस्ड आहार लेने से मोटापा, चयापचय बिगड़ना और अतिरिक्त जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।



रात को दांत ब्रश करना क्यों आवश्यक और क्या फायदे, जाने

रात को दाँत ब्रश करना उतना साधारण नहीं है जितना लोग समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह साबित कर रहा है कि अगर हम सोने से पहले ब्रश नहीं करते, तो मुँह में हानिकारक बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया मसूड़ों में सूजन पैदा करते हैं, और यह सूजन रक्त प्रवाह के साथ पूरे शरीर में फैलकर दिल पर असर डाल सकती है। मुँह और दिल का यह संबंध अब चिकित्सा विज्ञान में अच्छे से स्थापित हो चुका है।
नींद के दौरान लार (saliva) कम बनती है, जबकि लार मुँह को साफ रखने का प्राकृतिक तरीका है। कम लार के कारण बैक्टीरिया रात भर आसानी से बढ़ते हैं। अगर रात में ब्रश नहीं किया जाए तो मुँह में बने वाले बैक्टीरिया मसूड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और सूजन पैदा करते हैं। समय के साथ यही



1. रात में सिर्फ दो मिनट ब्रश करना प्लाक हटाता है, मसूड़ों की सूजन कम करता है, और पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को स्वस्थ बनाए रखता है। फ्लोरिडिंग और नियमित डेंटल चेकअप इस सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। ये छोटे-छोटे आदतें बैक्टीरिया को नियंत्रित रखती हैं और दिल पर बोझ कम करती हैं।
2. रात का ब्रश एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े हैं। यह सिर्फ आपके मुस्कान की रक्षा नहीं करता, बल्कि आपकी धमनियों और आपके हृदय को भी मजबूत बनाता है। मुँह की देखभाल करना, वास्तव में पूरे शरीर की देखभाल है। आपकी रात की दिनचर्या आपकी सोच से ज्यादा प्रभाव डालती है। दिल की सुरक्षा कई बार एक दृष्टिकोण से ही शुरू हो जाती है।

सूजन रक्त में पहुँचकर: 1. शरीर में सूजन के स्तर बढ़ा सकती है 2. धमनियों को कठोर या संकरी बना सकती है 3. दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।
कई अध्ययनों ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया है कि खराब ओरल हाइजीन से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, अच्छी बात यह है कि यह जोखिम पूरी तरह टाला जा सकता है।

मसूड़ों की बीमारी दिमाग तक पहुँचकर पहुँचा सकती है बड़ा नुकसान, जाने

वैज्ञानिकों ने पाया कि मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले कुछ बैक्टीरिया कभी-कभी दिमाग तक पहुँच जाते हैं। ये बैक्टीरिया जहरीले पदार्थ बनाते हैं, जो Alzheimer's रोग से पीड़ित लोगों के दिमाग में पाए गए।
चूँकि पर किए गए प्रयोगों में देखा गया कि जब ये बैक्टीरिया मुँह में थे, कुछ समय बाद वे दिमाग में भी पहुँच गए और Alzheimer's जैसी क्षति बढ़ गई।
जब वैज्ञानिकों ने इन जहरीले पदार्थों को रोकने वाली दवा दी, तो दिमाग में सूजन कम हुई, नुकसान करने वाले प्रोटीन कम बने और दिमाग की कोशिकाएँ सुरक्षित रहीं।
इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मसूड़ों की बीमारी से Alzheimer's होता है। लेकिन यह



दिखाता है कि कई वर्षों तक चलने वाला मसूड़ों का संक्रमण दिमाग को नुकसान पहुँचा सकता है।
सीधी बात: मसूड़ों की सफाई और सेहत दिमाग की सुरक्षा में भी मदद कर सकती है।

दाँतों को गैर-प्रमुख हाथ (non-dominant hand) से ब्रश करना



दाँतों को गैर-प्रमुख हाथ (non-dominant hand) से ब्रश करना भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन यह दिमाग को गहरी कसरत देता है। यह छोटी-सी आदत दिमाग को नए तरीके से काम करने पर मजबूर करती है, जिससे दोनों हेमिस्फियर के बीच तालमेल बेहतर होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी — यानी नई न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता — मजबूत होती है।
ऐसे "डुअल-टास्क" अभ्यास ध्यान, वर्किंग मेमोरी और मानसिक लचीलेपन को बेहतर बनाते हैं।
समय के साथ ये छोटे-छोटे ब्रेन वर्कआउट ग्रे मैटर की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम कर सकते हैं।
हर दिन ऐसे छोटे, अनजान मूवमेंट करते रहने से आपका दिमाग सक्रिय, अनुकूलनशील और मजबूत बना रहता है।



हेल्थ केयर, घरेलू नुस्खे, मूंगफली और गुड़ एक हेल्दी कॉम्बो जो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए

ऐसे कई फूड्स हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और अगर आप दो ऐसे पोषक फूड्स को मिलाते हैं, तो आपको एक सुपर हेल्दी और पावरफुल ट्रीट मिलेगी। सर्दियों के लिए ऐसा ही एक आइडियल कॉम्बिनेशन है गुड़ में लिपेड पीनट बॉल्स या चिकनी जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि भूख मिटाने और शरीर को मजबूत बनाने का भी एक शानदार तरीका है।
मूंगफली में सेलेनियम, और गुड़ में मैग्नीशियम और आयर्न फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
यह स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने और एनीमिया से बचाने में मदद करता है। मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून को साफ करने में भी मदद करते हैं।

तिल का प्रयोग, तथ्य—आधारित

तिल के बीज हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोतों में से एक हैं। छोटी मात्रा में ही इनमें अधिक कैल्शियम, साथ ही मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और विटामिन B6 पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती और ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं।
जिंक कोलेजन बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत और जोड़ लचीले रहते हैं। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को संतुलित रखने में भी सहायक होते हैं।
प्रतिदिन एक चम्मच तिल या ताहिनी आसानी से मिनरल-इंटेक बढ़ा सकती है।
मजबूत हड्डियाँ नियमित आदतों से बनती हैं — पीनट भोजन, धूप, हलचल और स्ट्रेच-ट्रेनिंग। तिल इनमें एक सरल और प्रभावी जोड़



है।
कई पोषण संबंधी अध्ययन और विश्लेषण बताते हैं कि तिल के बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि खनिजों का अच्छा स्रोत हैं, जो हड्डियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा, तिल में मौजूद एक यौगिक सेसमिन (Sesamin) पर प्रयोगशाला स्तर पर किया गया अध्ययन दिखाता है

रूप से तार्किक और लाभदायक आहार विकल्प बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। फिर भी, चूँकि तिल (विशेषकर बिना छिले/भिगोए हुए) में फाइबर और ऑक्सलेट जैसे "एंटी-न्यूट्रिएंट" होते हैं, कैल्शियम का अवशोषण पूरी तरह नहीं हो पाता। इसलिए, यदि आप तिल से लाभ लेना चाहते हैं, तो: रोज एक-दो चम्मच तिल बीज (बहुत ज़्यादा नहीं) लें, तिल को हल्का भून कर या भिगोकर खाएँ (जिससे एंटी-न्यूट्रिएंट घट जाते हैं), और इसके साथ विटामिन D (धूप/संतुलित आहार), सम्पूर्ण पोषण व स्वस्थ जीवनशैली रखें।
यह दुष्टिकोण — किसी "फास्ट-फिक्स" की दलील नहीं — बल्कि एक संतुलित, वैज्ञानिक रूप से समर्थित, दीर्घकालिक पोषण रणनीति के रूप में उपयोगी है।

सर्दियों में त्वचा की सुरक्षा अत्यंत उपयोगी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित

सर्दियों में त्वचा की सुरक्षा: विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आधुनिक और प्रभावी उपाय



सर्दियों की शुष्क हवा, ठंडी हवाएँ और घरों में चलने वाली हीटर की गर्मी—ये तीनों मिलकर त्वचा के प्राकृतिक नमी-संतुलन को तेजी से कम कर देते हैं। परिणामस्वरूप त्वचा में खुजली, रूखापन, पपड़ी, फटने जैसी सामान्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं। कई बार यह साधारण सूखापन एक्जिमा (Dry Eczema) या डर्मेटाइटिस जैसी गंभीर स्थितियों का रूप भी ले सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ सरल और नियमित आदतें अपनाकर इन समस्याओं को आसानी से रोका जा सकता है। त्वचा विशेषज्ञों के नवीनतम सुझावों के आधार पर प्रस्तुत हैं सर्दियों में त्वचा को सुरक्षित रखने के अद्भुत और प्रभावी उपाय—
1. नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएँ — और दिन में 2-3 बार लगाएँ। विशेषज्ञों का मानना है कि त्वचा गीली हो, उसी समय क्रीमी (Cream-based) मॉइस्चराइजर लगाने से नमी "सील" हो जाती है। लोशन की जगह थिक क्रीम, बॉडी बटर या मलहम (ointment) अधिक प्रभावी होते हैं।
2. Ceramides, Hyaluronic Acid, Shea Butter और Glycerin वाले उत्पाद त्वचा में नमी को बंधकर रखते हैं। बहुत अधिक रूखे हिस्सों—जैसे पैर, एड़ियाँ, कोहनियाँ, हाथ—पर Petroleum Jelly लगाया श्रेष्ठ माना जाता है।
नवीनतम जानकारी: 2024-25 की डर्मेटोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि Ceramide-rich moisturizers नियमित उपयोग से त्वचा की सुरक्षा परत (Skin Barrier) को 50% तक मजबूत कर देती है।
2. कम समय और गुनगुने पानी से नहाएँ
1. 5-10 मिनट का गुनगुने पानी

से स्नान आदर्श माना गया है।
2. बहुत गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेलों को नष्ट कर देता है।
3. साबुन की जगह सिंडेट (Syndet) या Mild Cleanser का उपयोग करें, और इसे केवल उन्हीं क्षेत्रों पर इस्तेमाल करें जहाँ अधिक गंदगी या पसीना हो।
4. त्वचा को तौलिये से हल्के हाथ से थपथपा कर सुखाएँ, रगड़ें नहीं।
3. घर के वातावरण में नमी (Humidity) बनाए रखें
1. सर्दियों में घरों के अंदर हवा बेहद सूखी हो जाती है।
2. कमरे में Humidifier चलाने से त्वचा को नमी सामान्य रहती है।
3. आदर्श नमी स्तर: 30-50%, यह त्वचा की पपड़ी, खुजली और फटने की समस्या को 40-60% तक कम कर देता है।
नवीनतम ट्रेड: Smart Humidifiers — जो कमरे के नमी स्तर को ऑटोमैटिक नियंत्रित करते हैं—त्वचा विशेषज्ञों द्वारा 2025 के लिए highly recommended हैं।
4. बाहर निकलते समय त्वचा की रक्षा करें
1. ठंडी हवा और तेज़ सर्द हवाएँ

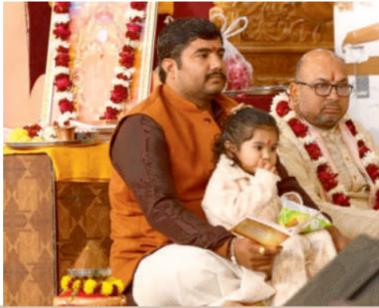
त्वचा को तुरंत नुकसान पहुँचाती है।
2. बाहर निकलते समय स्कार्फ़, ग्लव्स, कैप अवश्य पहनें।
3. सर्दियों में भी SPF 30+ Sunscreen आवश्यक है, क्योंकि UV किरणें बर्फ और धूल से परावर्तित होकर त्वचा को नुकसान पहुँचाती हैं।
नवीनतम शोध: Dermatology Research के अनुसार, सर्दियों में सनस्क्रीन न लगाने से त्वचा का सूखापन 25-30% तक बढ़ जाता है।
5. शरीर को भीतर से हाइड्रेट रखें
1. ठंड में प्यास कम लगती है, परंतु शरीर को नमी की आवश्यकता बराबर रहती है।
2. दिन भर में पर्याप्त पानी, साथ ही फल, सब्जियाँ, नारियल पानी, सूप आदि का सेवन करें।
3. ओमेगा-3 युक्त आहार (अखरोट, अलसी, चिया सीड) त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं।
6. एक्सफोलिएशन कम करें और त्वचा को शांत रखें
1. कड़े स्क्रब, अल्कोहल बेस्ड टोनर, सुगंधित लोशन—ये सभी सर्दियों में त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं।
2. यदि एक्सफोलिएशन आवश्यक हो तो मुलायम कपड़ा या

बहुत हल्का स्क्रबर सप्ताह में एक बार उपयोग करें।
3. ध्यान रहे: लक्ष्य है Scrub करनी नहीं, Hydrate और Protect करना है।
कब डॉक्टर से संपर्क करें? यदि आपको यह लक्षण दिखें—
1. बहुत तेज़ खुजली
2. त्वचा में गहरी लालिमा
3. पपड़ीदार दागे
4. फटी त्वचा में जलन या दर्द
5. रात में नींद प्रभावित होना तो यह Eczema या Dermatitis का संकेत हो सकता है। डॉक्टर Prescription Creams, Barrier Repair Therapy, या Short-term Steroids देकर जल्दी राहत देते हैं।
समय है इसे तुरंत अपनाने का, दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य तक त्वचा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। अभी से ये आदतें शुरू करने पर—
1. त्वचा नर्म, कोमल और चमकदार बनी रहती है
2. फटने या एक्जिमा जैसी समस्याएँ नहीं होतीं
3. सर्दियों का मौसम ज़्यादा आरामदायक गुजरता है

सुन्दरकाण्ड पाठ से शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं श्रीहनुमानजी महाराज : अनिरुद्धाचार्य महाराज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम में मां सीता रसोई के सौजन्य से श्रीहनुमद् आराधन मण्डल के द्वारा प्रमुख समाजसेवी रंजना रत्नर बहिन मनप्रीत कौर (लुधियाना) के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुंदर काण्ड का संगीतमय सामूहिक पाठ किया गया जिसमें कई प्रख्यात सन्तों, विद्वानों, धर्माचार्यों एवं तमाम भक्तों-श्रद्धालुओं ने भी बह-चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष व विश्वविख्यात भागवताचार्य डॉ. अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। इस पाठ को करने से श्रीहनुमानजी महाराज शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवताचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री एवं प्रख्यात साहित्यकार रंजना रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि श्रीहनुमानजी महाराज भक्ति शिरोमणि हैं। कलिकाल में श्रीहनुमानजी की आराधना के बिना भागवान श्रीरामजी की भक्ति प्राप्त कर पाना असम्भव है। मां सीता रसोई की संचालिका रंजना रत्नर बहिन मनप्रीत कौर (लुधियाना) एवं प्रबंधक आचार्य अंशुल पाराशर ने कहा कि श्रीहनुमानजी महाराज समस्त सद्गुणों की खान हैं। उनमें वीरता, स्वामी भक्ति, बुद्धि-ज्ञान आदि का भंडार है। जो व्यक्ति जिस कामना से उनकी पूजा-अर्चना करता है, उसकी कामना व निश्चित ही पूर्ण करते हैं। कार्यक्रम में श्रीहनुमद् आराधन मण्डल के अध्यक्ष अशोक व्यास, बागेश्वर धाम के परम-लाडले आचार्य रोहित रिछारिया, आचार्य ब्रह्मराज महाराज, धर्म पथिक शैलेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य विमल कृष्ण पाठक, आचार्य शिवम साधक, आचार्य अश्विनी मिश्रा, आचार्य श्रीराम मुद्गल, आचार्य बुद्धिप्रकाश



शास्त्री, श्याम सुन्दर ब्रजवासी, स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, सन्त रामदास महाराज (अयोध्या), आचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा, चैतन्य किशोर कटार, स्वामी रामशरण शर्मा, स्वामी प्रेमशरण शर्मा, आचार्य मुकेश मोहन शास्त्री, आचार्य घनश्याम दुबे, धर्मवीर शास्त्री, प्रियाशरण भक्तमाली, बाल व्यास ध्रुव शर्मा एवं आचार्य विजिन बापू आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन आचार्य सुमंत कृष्ण महाराज ने किया। धन्यवाद ज्ञापन व आभार व्यक्त आचार्य अंशुल पाराशर ने किया। बहिन मनप्रीत कौर ने आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों को कंबल सप्रेम भेंट किए।



कार्यक्रम का समापन सन्त, ब्रजवासी, वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ

हुआ जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार



स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (सदरन रेंज) ने अवैध हथियारों की सप्लाई लाइन तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 11 उच्च गुणवत्ता की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई हैं। ये हथियार मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को सप्लाई किए जाने थे। स्पेशल सेल को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और एनसीआर के गैरस्टर व शांतिर अपराधी मध्य प्रदेश स्थित हथियार निर्माताओं और डीलरों से अवैध हथियार मंगवा

रहे हैं। इसी कड़ी में स्पेशल सेल/सदरन रेंज की एक टीम, जिसका नेतृत्व इस्पेक्टर रंजीत सिंह और इस्पेक्टर संजीव कुमार कर रहे थे तथा जो एसीपी नीरज कुमार की निगरानी में काम कर रही थी, पिछले एक महीने से इस नेटवर्क की पहचान और भंडाफोड़ में जुटी हुई थी। लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन के बाद गिरोह के कुछ सदस्यों की पहचान की गई। इसी दौरान 9 दिसंबर 2025 को स्पेशल सेल को एक पुख्ता सूचना मिली कि इस हथियार तस्करी सिंडिकेट का एक सदस्य मनपाल, मध्य प्रदेश के सेंधवा से अवैध पिस्टलों की खेप लेकर दिल्ली आ रहा है और इन्हें सराय काले खां क्षेत्र में सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर इस्पेक्टर रंजीत सिंह के

नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर जाल बिछाया गया। 9 दिसंबर की देर रात संदिग्ध व्यक्ति को चिह्नित कर घेराबंदी की गई और उसे काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 11 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (32 बोर) और 11 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनपाल पुत्र कल्याण, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिजलीपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना स्पेशल सेल में एफआईआर संख्या 302/25, दिनांक 10.12.2025, धारा 25/25(8) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पृष्ठताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह ये

पिस्टल मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित एक हथियार सप्लायर से खरीदता था और उन्हें दिल्ली व एनसीआर के अपराधियों को बेचता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अब तक 25 से अधिक अवैध पिस्टल मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न अपराधियों को सप्लाई कर चुका है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से दिल्ली और एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल सेल (सदरन रेंज) श्री आलाप पटेल द्वारा जारी प्रेस विज्ञापन में दी गई।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना का संबोधन - राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन है वंदे मातरम

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश, संजय सिंह। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने इसे राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बताते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को विनम्र नमन किया।

वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा कि वंदे मातरम हमारी पहचान, हमारी आपसी एकता और हमारे सामूहिक भविष्य का प्रण है। वीरों का बलिदान केवल इतिहास नहीं, राष्ट्र की अनंत प्रेरणा शक्ति है। उन्होंने तीन सूत्रों को याद रखने पर बल दिया आपसी एकता हमारी शक्ति, बलिदान हमारा मार्ग और भारत माता हमारी आत्मा है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, तपस्या और मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम की गुंज इस गीत की हर पंक्ति में आज भी सुनाई देती है। यही कारण है कि वंदे मातरम ने दासता के अंधकार में करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित रखी।



वरिष्ठ समाजसेवी ने महान तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के उस विचार का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का स्वर विश्व भर में तेजस्विता और आपसी एकता का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से निकला यह कालजयी गीत उस दौर में जन्मा जब मातृभूमि पर उपनिवेशवाद का भारी प्रतिबंध था, लेकिन यह देखते ही देखते पूरे राष्ट्र को साझा धड़कन बन गया। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि

भारत माता के प्रति अदम्य साहस, त्याग और समर्पण की शाश्वत भावना है।

समापन में वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने स्मरण कराया कि यह गीत धर्म, मजहब, भाषा और भौगोलिक सीमाओं से परे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता आया है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वंदे मातरम केवल प्रेरणा नहीं था यह वीरों की अंतिम पुकार था, जब वे हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए मातृभूमि के स्वप्न को हृदय में लिए इसे उच्चारित करते थे।

लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बना शोपीस! लटकते ताले

परिवहन विशेष न्यूज

बंदायु ग्रामीणों का आरोप पंचायत घर पर लगे रहते ताले आवश्यक कार्य पर भी समय भी नहीं खुलता पंचायत घर गांव में लगे सरकारी हैडपंप पड़े हैं खराब, बार बार शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान पर ठीक न कराने का आरोप गांव में सफाई न होने के कारण पनप रही गंदगी। कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर है

ग्रामवासी व राहगीर गलियों में फैली गंदगी नाले, नालियों में कीचड़ से पनप रहे हैं जानलेवा मच्छर! जिसकी वजह से गाँव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा ग्राम प्रधान के मनमाने रवैया के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश जिम्मेदारों पर मनमानी और दबंगई के लगे गाँधी आरोप शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही!

स्वच्छता अभियान को लगातार पलीला लगा रहे जिम्मेदार! काम काज केवल कागजों तक सीमित। उच्च अधिकारियों को किया जा रहा है गुमराह R.R.C (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) पर लगाए जा रहे उपले खबर संबंधित वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल पूरा मामला इस्लामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़ेड़ा का है।

किताबों में बंद कहानियाँ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास का आधार हैं।

डॉ. मुस्ताकअहमद शाह

किताबें केवल कला के पन्नों का ढेर नहीं होतीं। ये मानव के संवेदों पर लगे अनुभव, ज्ञान, आशा और श्रद्धा का अमूल्य संचय होते हैं। कहानियाँ वास्तव में हमारे संस्कृति, सभ्यता और सोच की दर्पण होती हैं। जब हम कहानियों को अग्रगण्य देते हैं, तो हम अपने अतीत की यादगार और भविष्य की रोशनी से जुड़ते हैं। लेकिन जब हम इनके छोड़ देते हैं, तो हम अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपनी स्वयं से कट जाते हैं। कहानियाँ क्यों जरूरी हैं? 1. पहचान और पहचान से जुड़ना। कहानियाँ हमें हमारी प्रतीति पहचान से जोड़ती हैं। ये हमारे पूर्वजों के संकेत, रीति-रिवाज और नृणाओं को संजोकर, पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती हैं।

2. ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान। खाली बातों की जगह कहानियों के जरिये सीखना आसान और अस्तरदार होता है। इनमें ज्ञान और नैतिकता प्राकृतिक ढंग से समाहित होती हैं। 3. कल्पना और सृजन। जब हम कहानियाँ पढ़ते या सुनते हैं, तो हमारा मन कल्पना के नए सपनाघन खोजता है और जीवन के अज्ञानता से खोजता है। 4. समझ और संवेदना। दूसरों के अनुभवों, संकेतों और संकेतों से अलग होकर हमारे भीतर कल्पना विकसित होती है। यही भावना समाज को मानवता से जोड़ती है। कहानियाँ छोड़ देना, क्या खो बैठते हैं? कहानियों पढ़ना या सुनना बंद करने का अर्थ सिर्फ किताबें बंद करना नहीं है, बल्कि, अपनी जड़ों से कट जाना सामाजिक और नैतिक नृणाओं को भूल जाना कल्पना और स्वभावकता की शक्ति को खो देना बिना संस्कृतियों और विचारों से अज्ञान रा जग

और इस तरह सामाजिक चेतना में गिरावट आ जाना हम क्या कर सकते हैं? कहानियों को अपने और अपने बच्चों के जीवन में शामिल करें। परिवार और मित्रों के साथ कहानियाँ साझा करें, अपने अनुभव सुनाएं, दूसरों की कहानियाँ सुनें। नई किताबें पढ़ें और पुरानी, अधूरी कहानियों को फिर से पढ़ें। कहानियों से मिले सबक को अपने हर सोच के निर्णयों और व्यवहार में लाएं। कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है, वह हमारा होती है, सबक लेती है, भावना लेती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली विरासत होती है। किताबों में बंद कहानियाँ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास का आधार हैं। इन्हें पढ़ना, बोलना और समझना, खुद से जुड़ने और समाज से जुड़े रहने का सबसे सख्त और सुंदर तरीका है। कहानियाँ जीवन हैं, इनसे जितना जुड़े जाएँ, उतना ही अपनी अस्त पहचान, सभ्यता और चेतना से भी जुड़ते जाएँ।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 और समय-आधारित (टाइम-ऑफ-डे) टैरिफ-नियम, नीति और राष्ट्रीय ऊर्जा सुधार की नई दिशा-एक समग्र अंतरराष्ट्रीय-स्तरीय विश्लेषण

विजन 2047 में टाइम-ऑफ-डे टैरिफ व्यवस्था भारत को न केवल ऊर्जा दक्ष बनाएगी, बल्कि उसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की मुख्यधारा में भी स्थापित करेगी- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गौदिया महाराष्ट्र गाँविया - वैश्विक स्तर पर भारत का बिजली क्षेत्र अब एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक देश में बिजली बिलिंग की प्रणाली मुख्यतः यूनित-आधारित रही, जहाँ उपभोक्ता द्वारा खपत की गई कुल बिजली के आधार पर शुल्क तय होता था, समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता था। किंतु बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और ग्रिड प्रबंधन को जटिलताओं ने इस परंपरागत मॉडल को अप्रसंगिक बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार और विद्युत नियामक संस्थाओं ने समय आधारित बिजली टैरिफ (टाइम ऑफ डे टैरिफ) को लागू करने का संभावित निर्णय की ओर अग्रसर है, जिसके तहत दिन, रात, सुबह और शाम अलग-अलग दरों पर बिजली बिल लगाया जाएगा। अगले 3 से 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है। यह परिवर्तन कोई तात्कालिक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, टैरिफ नीति संशोधन, और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित रणनीति हैं। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गौदिया महाराष्ट्र यह मानता है कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 को आधुनिक बिजली व्यवस्था की आवश्यकता और ऊर्जा संक्रमण की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप तैयार किया गया एक प्रमुख सुधारात्मक प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य विवरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

बढ़ाना, नियामकीय ओवरसाइट सुदृढ़ करना और उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार भुगतान के लिए प्रेरित करना है। विधेयक की यह नींव पारंपरिक यूनित-टैरिफ मॉडल से हटकर मांग-आधारित समय-संवेदी कीमत निर्धारण की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसका सबसे निर्णायक उपकरण समय-आधारित टैरिफ है। विधेयक की प्रमुख धारणाएँ, टीओडी टैरिफ का वैज्ञानिक व आर्थिक तर्क, कार्यान्वयन चुनौतियाँ स्मार्ट मीटरिंग और पीएचए, अलग समय पर अत्यंत असमान रहती हैं। पीक आवसर्ग में ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है, महंगे पावर प्लांट चालू करने पड़ते हैं और कभी-कभी बिजली कटौती तक करनी पड़ती है। इसके विपरीत ऑफ-पीक समय में उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा निरर्थक रहता है। टीओडी टैरिफ का उद्देश्य मांग को संतुलित करना, ग्रिड स्थिरता बढ़ाना, और उपभोक्ताओं को समय के अनुसार खपत बदलने के लिए प्रेरित करना है। भारत में

बिजली क्षेत्र का मूल कानूनी ढांचा विद्युत अधिनियम, 2003 (इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003) है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बिजली उत्पादन, वितरण और टैरिफ निर्धारण के लिए व्यापक अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 61 और 62 विशेष रूप से टैरिफ निर्धारण से संबंधित हैं, जिनमें कहा गया है कि टैरिफ आर्थिक दक्षता, उपभोक्ता हित, और संसाधनों के कुशल उपयोग को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। समय आधारित टैरिफ इसी अधिनियम की भावना के अनुरूप है, क्योंकि यह बिजली की खपत के बेहतर उपयोग और लागत-आधारित मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित करता है। अधिनियम किसी एक समान दर को बाध्यता नहीं लगाता, बल्कि नियामक आयोगों को नवाचार की स्वतंत्रता देता है। साधियों बात अगर हम राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 और 2023 संशोधन की भूमिका इसको समझने की करें तो, टाइम-ऑफ-डे टैरिफ को वास्तविक रूप से अनिवार्य बनाने का कार्य राष्ट्रीय टैरिफ नीति (टैरिफ पॉलिसी) के माध्यम से किया गया। 2016 की टैरिफ नीति में पहली बार संकेत दिया गया कि बड़े उपभोक्ताओं के लिए समय आधारित टैरिफ अपनाया जाना चाहिए। किंतु यह प्रावधान सीमित और वैकल्पिक था। वास्तविक परिवर्तन 2023 में किए गए टैरिफ नीति संशोधन से आया। इस संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि, डिस्कॉ को सभी उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू करना होगा। (1) स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था प्राथमिकता से लागू की जाएगी। (2) राज्य विद्युत नियामक आयोगों को पीक और ऑफ-पीक घंटों की अधिसूचना करनी होगी। यह संशोधन ही वस्तुतः



नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग-अलग स्लेब में बंटा होगा

नीति आधार है जिसके तहत अब देश भर में दिन-रात के हिसाब से बिजली दरें तय की जा रही हैं। साधियों बात अगर हम राष्ट्रीय विद्युत नीति और ऊर्जा संक्रमण का संदर्भ, राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका, इसको समझने की करें तो, भारत की राष्ट्रीय विद्युत नीति का मूल उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय और सतत बिजली उपलब्ध करना है। नीति यह स्वीकार करती है कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी। चूंकि ये स्रोत समय-निर्भर होते हैं, इसलिए पारंपरिक फ्लैट टैरिफ उनको अनुकूल नहीं है। दिन में जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, उस समय बिजली सस्ती होनी

चाहिए। वहीं रात में, जब सौर उत्पादन नहीं होता, दरें स्वाभाविक रूप से अधिक होंगी। टीओडी टैरिफ इसी तार्किक ऊर्जा संतुलन को लागू करता है। टाइम-ऑफ-डे टैरिफ बिना स्मार्ट मीटर के संभव नहीं है। इसी कारण भारत सरकार ने रोवैड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कैम (आरडीएसएस) के तहत करोड़ों स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को बिजली खपत को रियल-टाइम में ट्रैक करते हैं और यह बताने में सक्षम होते हैं कि किस समय कितनी बिजली उपयोग हुई। आरडीएसएस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य ही यह है कि टैरिफ को डायनेमिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जाए। टीओडी टैरिफ इसी योजना का स्वाभाविक परिणाम है। राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका-हालाँकि नीति और दिशा-निर्देश केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन वास्तविक टैरिफ निर्धारण का अधिकार राज्य विद्युत नियामक आयोगों के पास होता है। प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक, आर्थिक और खपत पैटर्न के अनुसार पीक और ऑफ-पीक समय निर्धारित करेगा। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में पीक आवसर्ग अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत समान रहेगा - पीक वाले समय में महंगी बिजली और खाली समय में सस्ती बिजली। साधियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत की स्थिति इसको समझने की करें तो, टाइम-ऑफ-डे टैरिफ कोई भारतीय प्रयोग नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह प्रणाली वर्षों से लागू है। इन

देशों के अनुभव बताते हैं कि टीओडी टैरिफ से (1) पीक डिमांड में 10-20 प्रतिशत तक कमी आई (2) ग्रिड फ्लेक्सीबिलिटी और ब्लैकआउट की घटनाएँ घटीं (3) उपभोक्ताओं की ऊर्जा दक्षता बढ़ी, भारत अब उसी वैश्विक ऊर्जा सुधार पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने समाजिक-आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए। उपभोक्ताओं पर प्रभाव, अवसर और चुनौतियाँ, इस नई प्रणाली से उपभोक्ताओं को यह समझना होगा कि बिजली अब केवल कितनी नहीं, बल्कि कब उपयोग की जा रही है। जो उपभोक्ता वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, चार्जिंग और अन्य भारी उपकरण ऑफ-पीक समय में चलाएँ, उनके बिल कम होंगे। हालाँकि शुरुआती दौर में जागरूकता की कमी, तकनीकी समझ और व्यवहारिक बदलाव चुनौती बन सकते हैं। इसलिए नीति में स्पष्ट किया गया है कि टीओडी टैरिफ क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा, न कि एक झटके में। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएँगे कि नियम आधारित सुधार, न कि तात्कालिक नियंत्रण, भारत में समय आधारित बिजली टैरिफ किसी एक आदेश या घोषणा का परिणाम नहीं है। यह विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति (संशोधित 2023), राष्ट्रीय विद्युत नीति, और आरडीएसएस जैसी योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से उभरा एक संरचनात्मक सुधार है। यह प्रणाली भारत को न केवल ऊर्जा दक्ष बनाएगी, बल्कि उसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में बिजली केवल स्थितिपत करेगी। अने वाले वर्षों में बिजली केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि समय-संवेदी आर्थिक संसाधन बन जाएगी—और यही इस ऐतिहासिक बदलाव का मूल उद्देश्य है।

मूर्खता के मंत्र से धूर्तता की साधना (अलेख : बदल सरोज)

इस सप्ताह शुरुआत राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कुछ लोग उनकी पार्टी के रेवड़ में अलग तरह की – कम मरखनी, कम कटखनी प्रजाति -- का मानते हैं। शायद इसलिए कि राजनीति में अनेक पदों पर रहने के अनुभवों के अलावा वे पढ़े-लिखे भी माने जाते हैं, उनकी डिग्रियां असली हैं, कम-से-कम अभी तक उनको लेकर कोई शकोसूबा नहीं है। भौतिकशास्त्र के व्याख्याता भी रहे हैं और अक्सर अटल बिहारी वाजपेई के अंदाज में बोलने की भी सयास, किन्तु असफल कोशिश करते रहते हैं। जो भले और भोले लोग अटल जी को अलग निराकार, निर्गुण कोटि का भाजपाई मानते थे, वे ही इनमें भी भिन्नता देखते हैं। तो इस बार शुरुआत इन्हीं ने की, यूं भी कह सकते हैं कि इन्हीं से करवाई गयी।

गुजरात के वडोदरा में एक सभा में उन्होंने रहस्योद्घाटन–सा करते हुए दावा किया कि: “देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाना चाहते थे, लेकिन सरकार पटेल ने नेहरू के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया।” विडम्बना यह थी कि इस तरह की साफ़-साफ़ विधाननकारी बातें वे उस सभा में बोले, जिसे ‘एकता रैली’ बताया गया था। इस बयान के बाद, इसके खंडन में आये अनेक दस्तावेजी सबूतों, जिनकी कोई सफाई इनकी तरफ से नहीं आई, को छोड़ भी दें, तो अत्यंत सरल–सी बात यह थी कि जिस कालखंड का वे जिक्र कर रहे थे, तब तक बाबरी मस्जिद सलामत थी, लिहाजा उसके बनाने या बनवाने का सवाल ही नहीं उठता था।

मगर उन्हें इस सबसे क्या : उन्हें इस अज्ञानता के सार्वजनिक इजहार के साथ जो करना था, वह उन्होंने कर लिया : बाबरी मस्जिद के गिराने की यह दादिलाते हुए धुवीकरण की मथनी में एक झोंटा लगा दिया। मूर्खता को साधना की तरह इस्तेमाल करके असाध्य को साधने की कला, जिस कुनबे के राजनाथ सिंह हैं, उसने अच्छी तरह सध्याई हुई है। गुजरात में बोलते हुए भी वे इसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे।

इसी का एक और नमूना डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत में लगातर, अनवरत जारी गिरावट को लेकर दिए गए कुतर्कों में दिखा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अनूठा तर्क दिया कि रहमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रूपये से खरीदारी करते हैं। हमें डॉलर से कोई लेना-देना नहीं है, डॉलर महंगा ही या सस्ता,

हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने स्तरहीन अभिनय की तरह, उसी तरह की बेतुकी और सतही टिप्पणियों के लिए कुख्यात तिवारी जी को उनके ज्ञान की सीमा को देखते हुए कुछ छूट देने की सोची भी जा सकती है – मगर तब तक अच्छे-खासे शिक्षा संस्थान से अर्थशास्त्र की पढाई करने वाली और रुपये को अधोगति की तरफ ले जाने वाले विभागी की मुखियाइन, वित्त मंत्राणी निर्मला सीतारमण की उन्जित आ गयी, जिसमे उन्होंने इसे कोई ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं माना।

वे बोली कि रूपया अपना लेवल खुद ही बना लेगा। रूपये–डॉलर की कीमतों को लेकर विपक्ष में रहते हुए मोदी, भाजपा और स्वयं इनके द्वारा की गयी रसीली टिप्पणियों पर भी झाड़ू फेरते हुए निर्मला जी ने कहा कि तब आर्थिक हालात बिल्कुल अलग थे। भले ही रुपया कमजोर हुआ हो, लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।” हालांकि यह दावा वे तब कर रही थीं, जब आईएमएफ ने उनकी अगुआई वाले वित्त मंत्रालय के जीडीपी इत्यादि के आंकड़ों को गलत और अविश्वसनीय करार देते हुए उन्हें ‘सी’ ग्रेड की श्रेणी में डाल दिया था। उनके बोलते ही उनके बाकी अनुभव भी ज्ञान देने उतर पड़े। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रूपये की गिरावट को अनुलेखनीय घटना बताते हुए इसे आपदा में अवसर के मोदी सिद्धांत के तहत घरेलू मुद्रा को अपना स्तर खोजने की अनुमति देने वाला अवसर बताया, तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार जैसे कुछ विद्वान अर्थशास्त्रियों ने तो अर्थशास्त्र की अब तक की सारी समझदारियों को ही तक पर रख दिया और कहा कि ‘कमजोर रुपया वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि यह निर्यात को बढ़ावा देता है और अधिक रोजगार पैदा करता है’, का सिद्धांत भी उठल दिया।

मगर इस प्रतियोगिता में बाजी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मारी। मिथकों के अर्जुन को तरह उन्होंने सीधे निशाने पर वार करने की बजाय निशाना ही बदल दिया और एलान कर दिया कि डॉलर के मुकाबले उतार-चढ़ाव फालतू की बात है, असल में तो भारतीय रुपये की ताकत बढ़ रही है, वे यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने रूपये की इस ‘मजबूती’ का श्रेय भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के आकार और अन्य देशों के साथ बढ़ते व्यापार



को दिया है। यह भी बताया कि 35 से अधिक देशों ने व्यापार के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की अनुमति दी है, जिससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए स्थानीय मुद्रा या अमेरिकी डॉलर में मुद्रा बदलने की आवश्यकता कम हो गई है।

अब इतने आला दर्जे की ‘बुद्धिमताओं’ को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता : इनका स्मारक बनाकर मूर्त रूप देना भी बहुत जरूरी था, सो खुद सरकार ने हाथ बढ़ाया और प्रधानमंत्री का हाल मुकाम बदल कर उसे सेवा तीर्थ नम्बर बन का नाम दे दिया। नौ साल में यह तीसरा नामकरण था; पहले रेसकोर्स रोड से लोककल्याण मार्ग हुआ और अब तो तीर्थ ही बन गया। आखिर नेहरू से मुकाबले भी तो करना है।

आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बड़े-बड़े सार्वजनिक उद्योगों, निर्माणों और बांधों और चंडीगढ़, दुर्गापुर, भिलाई जैसे शहरों को भारत का आधुनिक तीर्थ बताया था – अब उनमें से ज्यादातर का मोदी जी अपने मित्र कारपोरेटों द्वारा भोग लगवा ही चुके हैं। मगर सेवा अभी अधूरी है, सो उसे पूरी करने के लिए मोदी ने खुद का पता ही सेवा तीर्थ वर भी नम्बर बन कर दिया। इसी की तुक में राजभवनों की भी लोकभवन बनाने की घोषणा भी कर दी गयी। ताजुब नहीं कि बात और आगे तक जाए और सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पंचों, सरपंचों के घरों–मकानों को भी छोटे–मोटे देवघाँओं या उनके गणों के नाम का तीर्थस्थल बता दिया जाए।

जिस दिल्ली में तीर्थ बनाया जा रहा था, उसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ताल से ताल मिलाई और दिल्ली की गलघोंटू हवा और प्रदूषण से

मुकाबले के लिए नयी शोध लेकर आ गयीं। उनका दावा रोचक था कि जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण हो, वहां – हॉटस्पॉट पर – पानी छिड़ककर उसे कम किया जा सकता है। इस ज्यादा ही हास्यास्पद शोधचिल्लीपन का बचाव करते हुए कुनबे की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आखिर एक्यूआई – वायु गुणवत्ता सूचकांक – भी तो एक तापमान की तरह हैर, इसलिए पानी का छिड़काव इसे कम करने का एक प्रभावी तरीका है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को किसी भी थर्मामीटर से मापे जाने योग्य एक तरह का तापमानह बताना बादलों की आड़ लेकर रडार को धोखा देने और नाली की गैस से चाय पकोड़ा बनाने जैसी ‘वैज्ञानिक खोजों’ की कड़ी में आगे की खोज है।

मूर्खत्व के यज्ञ में सप्ताह की आखिरी आहुति वंदे मातरम पर दिन भर की बहस थी। इसके जरिये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को जोड़ने वाले इस लोकप्रिय गान को जनता की एकता को तोड़ने के नफरती अभियान में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी गयी। खुलकर हिन्दू–मुसलमान किया गया। जिन्होंने जब वन्देमातरम देश को एकजुट कर प्रेरित और उत्साहित कर रहा था, तब उसका ‘व’ तक नहीं बोला, जिस आर एस ने अपने पूरे 100 साल में एक बार भी वन्दे मातरम नहीं गाया, उनका अचानक इस गान के प्रति अनुराग जिस कुत्सित इरादे से था, उसे उन्होंने छुपाया भी नहीं।

बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साम्प्रदायिक धुवीकरण को और तीखा करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बार–बार बंगाल का जिक्र करके एक तरह से खुद ही कबूल कर

लिया। उन्होंने देश भर के इस गान को बंगाल तक ही सीमित कर दिया। जिस उपन्यास का यह हिस्सा है, उस आनंदमठ के लेखक बंकिम बाबू की बंगाली पृष्ठभूमि के बखान से लेकर ‘पश्चिम बंगाल की मेधा पूरे देश को रास्ता दिखाया करती थी’, जैसे कई बोल-वचन से इस बहस के नफरती मंतव्य को साफ़ कर दिया। ध्यान रहे, यह बहस भी उस पटकथा का हिस्सा थी, जिसे एक दिन पहले मंचित किया गया था। इनसे, जिसकी अगले दिन संसद में दुहाई दी जा रही थी, वह वन्देमातरम नहीं गवाया गया, जिसकी कोई धार्मिक परम्परा नहीं है, जिसका किसी धार्मिक कर्मकांड में कोई प्रावधान तो दूर, उल्लेख तक नहीं है। वहाँ भगवद्गीता का सामूहिक पाठ कराया गया था।

यह वही धूर्ततापूर्ण पटकथा थी, जिसमें इधर बंगाली अस्मिता पर जोर देकर स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य के भद्र लोक के अहम योगदान को याद दिलाई जा रही थी, उधर मुस्लिम तुष्टीकरण और विभाजन की बात कर परोक्ष रूप से राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। इसी का परोक्ष हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ चुके, बाद में ममता की पार्टी में गए, अब निलम्बित, हुमायूँ कबीर से बाबरी मस्जिद फिर से बनवाने का अहद उठवाकर आग में तेल डलवाया जाना।

कुल मिलाकर यह कि पूरी निर्लेखजना और दीदादिलेरी के साथ विवेक हरने और अविवेक का वर्चस्व बनाने की साजिश तृप्तनी तेजी के साथ अमल में लायी जा रही है। ध्यान बंटाने के मनोविज्ञान में मूर्खता को एक उपयोगी संसाधन के

रूप में कर दिया गया है। मौजूदा हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि किन-किन तरीकों से किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का ध्यान असली हालात या विचार से कैसे हटाया जा सकता है। उन्हें पता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जानकारी संग्रह करने, उसका विश्लेषण करके दूध और पानी को अलग करने और केवल प्रासंगिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उनका सार ग्रहण करने की क्षमता सीमित होती है। जब ध्यान भटकता है, तो यह प्रक्रिया और भी बाधित होती है। नतीजे में अनावश्यक, यहाँ तक कि स्वयं उसके लिए भी घातक समझ दिमाग में घर बना लेती है। इाहरण दुःख देने के पहले मति हर लेना इसी को कहते हैं।

सत्ता में बैठा कांपैरिटी हिंदुत्व का गठजोड़ इसकी कारगरता को जानता है और उसके लिए खुद को मूर्ख दिखाने का भी संकोच या शर्म लिहाज नहीं करता। लोकप्रिय मुहावरे में इसे ‘ऐड़ा बनके पेड़ा खाना’ कहते हैं। पिछले सप्ताह में मूर्खताओं की इस बहार में छुपा कर पतझरों को लहलहाने का काम किया गया जिसकी मिसाल है। इाहरण वन्दे मातरम पर नफरती कोरस गाया जा रहा था, उधर भारत की खेती–किसानी की रीढ़ तोड़कर उसे हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीज–राक्षसों के मुनाफे की तिजोरियों में दफ़न करने देने वाला सोड बिल, 2025 लाया जा रहा था। बिना संसदीय प्रक्रिया का पालन किये, बिना बहस कराये, बिना किसी संसदीय समिति को भेजे, बिजली बिल, 2025 सहित एक के बाद एक जनविरोधी विधेयक धड़ाधड़ पारित किये जा रहे थे।

कुख्यात चार लेबर कोइस को लागू किये जाने के साथ शुरु हुआ हमला जनता के बाकी हिस्सों को भी अपनी कूपट में ले रहा था। बिहार में मिली जीत के बावजूद भी बुलडोजर दनदनीय लग्ये थे। इस कुहासे के बीच देश के सभी नागरिकों के मोबाइल फोन में जासूसी का एप्य बिठाने की कोशिश जा रही थी, जिसे समय रहते कम–से–कम फिनालह के लिए तो रोक दिया गया है। किन्तु आशंकाएं और गहरी हो गयी हैं।

दिखावे के लिए मूर्खता की आराधना करने वाले धूर्तता के साधकों की कार्यशैली को समझकर ही इन आशंकाओं से बचा जा सकता है। इसके लिए जानकारों ही बचाव है, आवाज उठाना ही उपचार है।

(लेखक ‘लोकजतन’ के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)

एक राष्ट्र, एक शिक्षा नियामक, एक विज्ञान: उच्च शिक्षा का नया युग

मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उनका संकल्प अटल है। 112 दिसंबर 2025 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विकसित भारत शिक्षा अधिधक्षण विधेयक के माध्यम से उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस विधेयक के तहत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे बिखरे हुए नियामक ढाँचों को समाप्त कर एकल और सशक्त उच्च शिक्षा नियामक की स्थापना की जा रही है। यह क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विकसित भारत @ 2047’ की परिकल्पना को ठोस आधार प्रदान करेगा, जहाँ शिक्षा केवल डिग्री अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। वर्षों से चली आ रही पुरानी विधेयकों में अन्यायों की टकराहट, स्वीकृतियों में निष्पक्ष विवेक और गुणवत्ता की असमानता ने छात्रों की प्रतिभा को सीमित किया था, एकल नियामक इन सभी बाधाओं को समाप्त कर सुशासन, पारदर्शिता और निर्यातक नेतृत्व की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

यह विधेयक, जिसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एआईसीआई) के नाम से जाना जाता था, अब विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण के रूप में नई पहचान और व्यापक दृष्टि के साथ सामने आया है। इस नए आयोग की तम प्रमुख भूमिकाएँ होंगी— विनियमन, प्रत्यायन और व्यावसायिक मानकों का निर्धारण। विनियमन के माध्यम से संस्थानों के संचालन, पाठ्यक्रम संरचना और नीतियों के अकरूपता आएगी, जिससे नवाचार और अकादमिक स्वतंत्रता को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रत्यायन व्यवस्था कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का पारदर्शी मूल्यांकन एवं रैंकिंग सुनिश्चित करेगी, जिससे छात्रों को सूचित और सही

निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। वहीं, व्यावसायिक मानक शिक्षण, तकनीकी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में समानता और उच्चतम स्थापित करेंगे। यह समय सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 2020 की भावना को साकार करेगा है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा, कौशल विकास और वैश्विक मानकों पर विशेष बल दिया गया है। मोदी सरकार की यह नीति इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह भावनात्मक नारेबाजी नहीं, बल्कि चरणबद्ध, संतुलित और व्यावहारिक सुधारों पर आधारित है। मेडिकल और विधि शिक्षा को नए नियामक के दायरे से बाहर रखकर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और संरचनाओं का सम्मान किया जाएगा। वर्तमान में फंडिंग से जुड़ी स्वायत्तता मंत्रालयों के पास बनाए रखना और भविष्य में इसे आत्मोपेक्षा के अधीन विधिपरिधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक का सुधार केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में उतरते दिख रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की अभूतपूर्व वृद्धि, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में निरंतर बढ़ोतरी और अनुसंधान बजट में रिकॉर्ड इज़ाफा—ये सभी उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी सरकार भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धी के लिए सक्षम बनाने के मिशन पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्रों के लिए यह परिवर्तन एक नई आशा और नए अवसरों का द्वार खोलता है। अब तक अनेक नियामकों की जटिल प्रक्रियाएँ

समय, ऊर्जा और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी का कारण बनती थीं—जहाँ तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई और सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी से अलग-अलग स्वीकृतियाँ लेनी पड़ती थीं। एकल छिड़की प्रणाली को लागू होने से अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी, पाठ्यक्रम अधिक लचीले बनेंगे और गुणवत्ता मानकों का समान रूप से पालन सुनिश्चित होगा। बहु-विषयक शिक्षा को वास्तविक अर्थों में बढ़ावा मिलेगा, जहाँ छात्र विना प्रशासनिक बाधाओं के इंजीनियरिंग के साथ कला या मानविकी जैसे विषयों का संयोजन चुन सकेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की खाई भी कम होगी, क्योंकि आईआईटी से लेकर छोटे कॉलेज तक सभी संस्थानों पर समान नियम लागू होंगे। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और

पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित करती है कि मोदी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ठोस परिणाम देने वाले साहसिक और पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा का यह ढाँचा उन करोड़ों छात्रों के लिए आशा को सशक्त आएगा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट और दूरगामी है—एक ऐसा भारत, जहाँ शिक्षा समावेशी हो, मानव को बढ़ावा दे, गुणवत्ता में वैश्विक मानकों को छुए और देश के हर युवा तक समान रूप से पहुँचे। इस विधेयक की स्वीकृति यह प्रमाणित

अमृतसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 30,298 मामलों का निपटारा



अमृतसर, 13 दिसंबर (साहिल बेरी)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय—सह-कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ए.एस.ए. नगर के मार्गदर्शन में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को विभिन्न न्यायालयों से भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि लोक अदालतों ने विवादों के त्वरित निपटारे और मामलों के शीघ्र समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लंबित मामलों में कमी आई है और न्याय तक पहुंच तेज हुई है। आज अमृतसर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 33,181 मामलों को सुनवाई हेतु लिया गया, जिनमें से 30,298 मामलों का निपटारा किया गया। निपटारा गए मामलों की कुल राशि 59,09,14,425/- रही, जो विवाद समाधान और वित्तीय वसूली में लोक अदालतों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। इस अवसर पर कुल 26 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें से 20 बेंच अमृतसर मुख्यालय में तथा 3-3 बेंच तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में स्थापित की गईं। अमृतसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन श्रीमती जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश—सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें श्री अमरदीप सिंह बैस, सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा सक्रिय प्रयास किए गए। लोक अदालत ने अपने मुख्य उद्देश्य—विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे और लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित समाधान—में सफलता प्राप्त की। प्री-लोक अदालत कार्यवाहियों के दौरान किए गए निरंतर प्रयासों और लोक अदालत के दिन प्रभावी आयोजन के कारण अमृतसर की विभिन्न अदालतों में कई वर्षों से लंबित सिविल और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों का निपटारा हुआ।

इनमें श्री अमरजीत सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)—सह-जे.एम.आई.सी., अमृतसर की अदालत में सिविल वसूली का मामला इलाहाबाद बैंक बनाम एम/एस पाल टेलर्स, जो वर्ष 2018 से लंबित था और वर्ष 2025-26 की प्रथम प्लान श्रेणी में शामिल था, का विधिवत निपटारा किया गया। बैंक द्वारा 6,05,561.40/- की वसूली का दावा किया गया था, परंतु अदालत के हस्तक्षेप से यह मामला 4,23,000/- में निपटारा हुआ। एक बड़ी राशि भौके पर अदा की गई और शेष राशि किस्तों में चुकाने पर सहमत बनी।

इसी प्रकार डॉ. गुरदर्शन सिंह, पी.सी.एस., सिविल जज (जूनियर डिवीजन)—सह-जे.एम.आई.सी., अमृतसर की अदालत में सिविल मामला एम/एस



सुरिंदर कोल सप्लाई बनाम एम/एस ए.पी. ऑटो पिस्टन इंजीनियरिंग, जो वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था और दलीलें पूर्ण होने तथा मुद्दे तय होने के बावजूद लंबित था, को प्री-लोक अदालत के दौरान किए गए निरंतर प्रयासों से सुलझा लिया गया।

सुश्री तरजानी, पी.सी.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमृतसर की अदालत में भी महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की गई, जहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लगभग नौ वर्षों से लंबित मामला एम/एस देवी दास एंड सन्स बनाम संजय खन्ना—जिससे संबंधित कई कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रही थीं—का निपटारा किया गया। अदालत के सशक्त प्रयासों से 16,25,000/- की राशि पर पूर्ण समझौता हुआ, जिससे लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी और सभी संबंधित कार्यवाहियों का अंत हुआ।

इसके अतिरिक्त, सुश्री नीलम, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, अमृतसर को देखरेख में वर्ष 2019 से 2021 तक लंबित रहे कई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों में चेक राशियां 20,000/- से 5,00,000/- तक थीं, जो पक्षकारों के बीच विवादों के कारण वर्षों से लंबित थीं। प्री-लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान

निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ताओं—जिसमें निजी पक्ष और वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं—की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार भुगतान किया गया।

इसके अलावा अजनाला में श्री पलविंदर सिंह, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दो वर्षों से अधिक समय से लंबित सिविल मामला विकास भाटिया एवं अन्य बनाम रणजीत सिंह एवं अन्य का भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान निपटारा किया गया। यह मामला लोक अदालत बेंच द्वारा सुना गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी के साथ श्री एच.एस. निज्जर, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अजनाला तथा श्री सुखचरणजीत सिंह, सचिव, बार एसोसिएशन, अजनाला शामिल थे। बेंच के प्रभावी हस्तक्षेप और विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से पक्षकारों की काउंसिलिंग की गई, जिससे समझौता हुआ और मामलों को वापस लेने के आदेशों के साथ अंतिम निपटारा किया गया।

इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित न्याय, वित्तीय वसूली, लंबित मामलों में कमी तथा पक्षकारों के बीच संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए एक प्रभावी मंच सिद्ध हुई। सभी न्यायालयों के संयुक्त प्रयासों से वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली सुदृढ़ हुई और न्याय तक पहुंच और अधिक सशक्त बनी।

मेयर भाटिया ने गुजराती पूजक समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में की शिरकत

अमृतसर 13 दिसंबर (साहिल बेरी)

अमृतसर — नगर निगम अमृतसर में आम आदमी पार्टी के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने गुजराती पूजक समाज द्वारा 09 ज्योतों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और माता रानी के समक्ष शोभा नवाया। इस अवसर पर मेयर भाटिया ने समस्त शहरवासियों की सुख-शांति, खुशहाली और प्रगति के लिए प्रार्थना की। गुजराती पूजक समाज के प्रधान बंसी लाल के नेतृत्व में 51वां वार्षिक जागरण पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसके उपरांत समाज की ओर से यह शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भजन और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

इस अवसर पर मेयर भाटिया ने कहा कि माता रानी की असीम कृपा से समाज में भाईचारे, आपसी सहयोग और सद्भावना की भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से



आयोजन लोगों को एकजुट करने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करते हैं। इस दौरान मेयर भाटिया ने शोभा यात्रा की सुचारु व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि गुजराती पूजक समाज द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के धार्मिक आयोजन अनुशासन और श्रद्धा के साथ करना अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से

जोड़ने के साथ-साथ समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। अंत में मेयर भाटिया ने गुजराती पूजक समाज के सभी सदस्यों को 51वें वार्षिक जागरण और शोभा यात्रा की हार्दिक बधाई दी और कहा कि नगर निगम अमृतसर सदैव धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए पूर्ण सहयोग करता रहेगा।

रेलवे स्टेशन अमृतसर ने एक व्यक्ति से 60 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

अमृतसर, 12 दिसंबर (साहिल बेरी)

दिनांक 12-12-2025 को एसआई राजेंद्र सिंह नं. 349 के नेतृत्व में एलआर/एसआई बलजेंद्र सिंह नं. 1383/जीआरपी, सीआईआई लव कुमार नं. 1037, एलआर/एसआई अवतार सिंह नं. 209, एलआर/एसआई अजय सिंह नं. 725 तथा कॉन्स्टेबल सुखविंदर सिंह नं. 377/जीआरपी की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन अमृतसर पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं तस्करो के खिलाफ चेकिंग की जा रही थी।

चेकिंग के दौरान करीब शाम 5:30 बजे, यात्री शेड के बाहर उत्तर साइड एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखकर अपनी पहनी हुई जींस पेट की जेब से काले रंग का मोमी लिफाफा निकालकर कूड़े के ढेर की ओर फेंक दिया और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को काबू कर



लिया। फेंके गए मोमी लिफाफे की जांच करने पर उसमें से 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम गौतम पुत्र स्व. रवि कुमार, निवासी दशरथ फौजी के किराए के मकान, गांधी कॉलोनी, गली नंबर 24, मॉडल टाउन,

पानीपत (हरियाणा) बताया। इस संबंध में थाना जीआरपी अमृतसर में मुकदमा नंबर 107 दिनांक 12-12-2025 धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को आज माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है।

टीएलएम मेला-3 का भव्य, प्रेरक एवं अत्यंत सफल आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

पताही/मोतिहारी। पताही प्रखण्ड अंतर्गत बेतौना संकुल में टीएलएम मटेरियल (टीएलएम) मेला-3 का आयोजन अत्यंत उत्साह, शैक्षणिक नवाचार और रचनात्मक वातावरण के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शैक्षणिक मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाना, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना तथा बाल केंद्रित शिक्षण को मजबूती प्रदान करना रहा।

टीएलएम मेले में संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों से प्रत्येक वर्ग के एक-एक छात्रने भाग लिया। बच्चों द्वारा अपने-अपने स्तर के अनुसार स्वयं तैयार किए गए टीएलएम मॉडल, चार्ट एवं नवाचारपूर्ण शिक्षण सामग्री मेले का मुख्य आकर्षण रहे। इन प्रदर्शनों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि बच्चों को उचित मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो वे सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट और प्रभावशाली शिक्षण सामग्री का निर्माण कर सकते हैं।

प्रदर्शनों में गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित विविध प्रकार के मॉडल और चार्ट लगाए गए। कहीं गणितीय अवधारणाओं को सरल रूप में दर्शाया गया था, तो कहीं विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़े प्रयोगात्मक मॉडल प्रस्तुत किए गए। भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के टीएलएम में कहानी, चित्र, मानचित्र और चार्ट के माध्यम से विषयवस्तु को रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। बच्चों की



मेहनत, कल्पनाशीलता, समझ और प्रस्तुति कौशल हर स्टॉल पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था।

टीएलएम मेला-3 के सफल आयोजन में सीआरसी बेतौना के संचालक गोबिंद कुमार सिंह एवं नतिश कुमार की प्रमुख भूमिका रही। इनके कुशल नेतृत्व, सतत मार्गदर्शन एवं बेहतर समन्वय के कारण कार्यक्रम व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ। साथ ही करुणाकर कुमार एवं पुष्पा कुमारी ने भी आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान दिया।

मेला के समापन से पूर्व संचालक गोबिंद कुमार सिंह द्वारा प्रदर्शित टीएलएम का सूक्ष्म

अवलोकन एवं मूल्यांकन किया गया। इसके पश्चात तीन उत्कृष्ट टीएलएम का चयन कर संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव एनपीएस बेतौना परती टोला को मिला। द्वितीय स्थान राजकीय मध्य विद्यालय गम्हरिया को प्राप्त समन्वय के कारण कार्यक्रम व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों एवं शिक्षकों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिससे अन्य बच्चों की भी भाविक्य में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली।

इस अवसर पर मृत्युंजय कुमार, अमित कुमार, मो. खुशींद आलम, सरोज ठाकुर,

बीरेन्द्र राम, हरिश्चंद्र कुमार साह, चंदा कुमारी एवं सपना कुमारी सहित कई शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सभी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए ऐसे आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कुल मिलाकर, टीएलएम मेला-3 न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने वाला आयोजन रहा, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण, रोचक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से विद्यालयों में नवाचार, सहभागिता और सीखने के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं।

अपनी जमीं खो दी...!

नहीं हो सकती 'असरदार विपक्ष' की कल्पना, कहे अश्विनी हर-बार न हो ईवीएम संकल्पना। पार्टी ने देश में कहीं-कहीं अपनी जमीं खो दी, बेअसर 'मुद्दे' ने भी चुनावों में लुटिया डूबो दी।

आइडियोलॉजी के लिए मन में बहुत इज्जत है, इस्तीफा इसलिए दिया हो रही हमें फज्जित है। अब भी नेताओं के लिए बहुत मन में सम्मान है, वह चुनाव जीत के ईवीएम से क्यों हलाकान है।

अब पार्टी को भीतर झांकने की है आवश्यकता, आज जवाब देने में भी नाकाम हो जाते प्रवक्ता। वाकई में ईवीएम में अगर कोई होती है गड़बड़ी, न लें चुनाव में हिस्सा जहां जीत रहे दो इस्तीफा।

(संदर्भ-अश्विनी कुमार का पार्टी से इस्तीफा)

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)



रिटायर्ड अधिकारियों पर सरकार का भरोसा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओईशिया

भूखनेश्वर : भर्ती में राज्य सरकार का यू-टर्न। रिटायर्ड अधिकारी फिर से होंगे, नौकरी ढूँढने वाले निराश रिटायरमेंट के बाद किसी को डबल अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है तो किसी को घर से लाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के टॉप इंजीनियर चंद्रशेखर पाद्री को जुलाई में रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के लिए OSD बनाया गया था। लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें फिर से नियुक्त किया जा रहा है। सवाल उठता है कि इतनी मेहरबानी क्यों? क्या विभाग में कोई काबिल नहीं है? एक को रिटायरमेंट के बाद दो बार अपॉइंटमेंट मिल रहा है। SC-ST विभाग से दो और लेटर आए। उन्हें घर से लाकर फिर से नियुक्त किया जा रहा है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर चित्तरंजन जेना को टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर सालाना अपॉइंटमेंट दिया गया है। बाबू इसके लिए हर महीने 75 हजार रुपये लेगे। वहीं, SC-ST विभाग के उस रिटायर्ड अधिकारी को। हालांकि, एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय कुमार मिश्रा को भी टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर सालाना अपॉइंटमेंट



दिया गया है। यहाँ सवाल यह उठता है कि राज्य में लाखों पढ़े-लिखे युवा नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी की उम्र कम होने से मानसिक तनाव के कारण कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन, नई पीढ़ी को मौके देने के बजाय सरकार बार-बार रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रख रही है। सरकार ने OSD के तौर पर जिम्मेदारी दी है। रिटायर्ड अधिकारियों की लिस्ट बनाने का ऑर्डर आया है कि वे किस डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए हैं। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। रिटायर्ड अधिकारियों पर सरकार का भरोसा। जल संसाधन विभाग के टॉप इंजीनियर का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट को धान हटाने के लिए किसान की मांग

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओईशिया

बरागढ़/भूखनेश्वर : बरागढ़ जिले में धान की कटाई का काम नॉर्मल नहीं रहा है। जिले की अलग-अलग मंडियों में बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। राजबोदासम्बा किसान संघ की ओर से पंचपुर सब-कलेक्टर के ऑफिस के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदित्य गौयल की मौजूदगी में, उन्होंने उनके पैरों तले धान फेंका और उनसे तुरंत सारा धान खरीदने की रिक्वेस्ट की। बताया जा रहा

है कि पिछले खरीफ सीजन में पंचपुर RMC से 30 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था। इस साल 92 धान खरीद केंद्र खोले गए हैं, लेकिन 42 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। अलग-अलग मंडियों में 3 लाख पैकेट धान पड़ा है, लेकिन सिर्फ 40 हजार पैकेट धान ही खरीदा गया है। 170% किसानों के टोकन अभी तक नहीं आए हैं, कई किसानों के टोकन जमीन से काफी कम आए हैं। कुछ टोकन जनवरी में बिकने वाले हैं। बिना सिंचाई वाले इलाकों के लिए प्रति एकड़

13 क्विंटल धान बेचने की इजाजत है। सरफ्लस धान का क्या करना है, इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। चुनावी वादा किया था कि धान का दाम 800 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 731 रुपये दिया जाएगा। ये सभी समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। बार-बार विरोध करने के बाद भी किसानों की शिकायत है कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। इससे किसान नाखुश हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे अगले सोमवार को धान लगाने के लिए मजबूर होंगे।



भाखड़ा ब्यास इंप्लाइज यूनिशन एटक ने की गेट मीटिंग

परिवहन विशेष न्यूज

संगरूर, (जगसीर लोगोवाल)- आज भाखड़ा भाखड़ा ब्यास इंप्लाइज यूनिशन एटक ऐफी शाखा संगरूर पटियाला कि गेट मीटिंग प्रधान श्री सरबजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस समय सम्बोधित करते हुए युनिशन महासचिव श्री सुरेश कुमार सैनी ने दिनांक 07 दिसंबर को हुई गंगुवाल बी बी एम ओफीसर क्लब में केंद्रीय कार्यकारणी की मीटिंग में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए सभी कर्मचारी साथियों को एक जुट होकर संघर्ष सील

होने की और सभी को आने वाली 25 दिसंबर के बाद काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करना तथा दिनांक 21 जनवरी 2026 को बोर्ड कार्यालय चंडीगढ़ में पहुंचने कि अपील भी कि गई। इस समय शाखा प्रधान श्री सरबजीत सिंह सहित उपसचिव श्री प्रकज वर्मा जी, संयुक्त सचिव श्री तिजेन्द्र पाल सिंह जी, श्री ओमप्रकाश जी, श्री रणजीत सिंह जी, श्री जगसीर सिंह ने भी अपने अपने विचार सांझा करते हुए मीटिंग में उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों को एकजुटता के साथ सहयोग देने हेतु अपील की।

